

programmes for the development of consumers co-operatives on comprehensive lines are being taken up. The discussions are at a very preliminary stage and no agreement has yet been reached regarding the nature of the assistance.

**खाद्यान्न का आयात**

१०११. श्री राम सेवक यादव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी० एल० ४८० के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका से मंगाया गया किन-किन वर्षों का खाद्यान्न का भण्डार मौजूद है ;

(ख) वह किस मात्रा में है ;

(ग) क्या १९५५ से अब तक सड़ा हुआ अन्न नीलाम हुआ ; और

(घ) यदि हाँ, तो किन-किन वर्षों में और कितना-कितना तथा नीलाम के भाव क्या थे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख) पी० एल० ४८० के अन्तर्गत प्राप्त तथा अन्य खरीद किए माल का अलग अलग हिसाब नहीं रखा जाता है । अतः नीचे दी गयी सूचना संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त कुल मौजूदा स्टॉक के बारे में है :—

(३१-७-१९६३ की स्थिति)

प्राप्ति वर्ष	खाद्यान्न (मात्रा हजार मीट्रिक टनों में)
१९६०	४
१९६१	१०
१९६२	३०२
१९६३	१२६७

(ग) और (घ). खराब दशा में प्राप्त खाद्यान्न या भण्डार अथवा मार्ग में खराब हुए खाद्यान्नों को प्रति वर्ष नीलाम कर दिया गया है । वर्ष के अनुसार मात्राओं का ब्योरा निम्नलिखित है :—

वर्ष	मात्रा (मीट्रिक टनों में)	दर (परास) (रुपये प्रति क्विन्टल, कुल)
१९५५	२६	३.३५ से १०.७२ तक
१९५६	१४८	४.३४ से १६.६६ तक
१९५७	७४०	२.६८ से १२.७४ तक
१९५८	४२७	२.०१ से १२.३६ तक
१९५९	७८१३	०.२५ से १२.१८ तक
१९६०	४८००	०.२५ से २५.५५ तक
१९६१	११४८८	०.२५ से २५.५५ तक
१९६२	५०९५	०.२५ से २५.५५ तक
१९६३	२४०८	०.२० से २५.५५ तक (जुलाई के अन्त तक)

**Aerodromes**

1012. Shri P. C. Borooah: Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state:

(a) whether Government have undertaken a major programme of improving aerodromes on regional routes all over the country to facilitate spread of air travels in the States;

(b) if so, the aerodromes in the North Eastern region which are to be improved under the scheme; and

(c) the major improvements to be made at these aerodromes

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Communications (Shri Ahmed Mohiuddin): (a) to (c). The question of lengthening/strengthening of runways at certain aerodromes on regional routes for operation by heavier and faster aircraft is under consideration.